मंगलवार, 11 अगस्त, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

तेज़ गेंदबाज़ भुवनेश्वर कुमार ने अपनी राय दी खुद को 'पूरी तरह तैयार' बताया

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

लोपामुद्रा राउत के घर 76 लाख की चोरी का खुलासा, बिहार से आरोपी गिरफ्तार

Page-05

JPSC-JSSC छात्रों का विधानसभा घेराव

पुलिस से झड़प के बाद आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल

- रांची सिटी SP पारस राणा के मुताबिक ज्यादातर छात्र शांतिपूर्ण थे, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
- छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार के साथ तीन दौर की बातचीत के बावजूद मांगें पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने आंदोलन जारी रखने और इसे जन-आंदोलन बनाने की बात कही।

रांची में JPSC-JSSC को लेकर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच फिर से झड़प हो गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। रांची सिटी SP पारस राणा ने कहा कि 90% छात्र शांतिपूर्ण हैं, लेकिन 10% किसी की बात नहीं मान रहे हैं। अगर भीड़ में 700-1000 छात्र किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, यहां तक कि अपने प्रतिनिधियों की भी नहीं, और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी है - बैरिकेडिंग को धकेलते हुए और तीन पुलिसकर्मियों को कुचलते हुए आगे बढ़े - फिर भी पुलिसकर्मियों ने संयम बरता। उन्होंने पुलिस बल पर पत्थर भी फेंके। फिर भी, हमने बहुत कम समय के लिए ही सख्ती दिखाई क्योंकि वे सभी छात्र हैं। राणा ने कहा कि मैं सभी से शांति बनाए रखने और हिंसा न करने की अपील करता हूं। आपकी मांगें सरकार तक पहुंच रही हैं, आक्रामक न हों... हम छात्रों से अपील करते हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें और पुलिस पर पत्थर न फेंकें। JPSC-JSSC परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों ने रांची में आंदोलन में शामिल सभी छात्रों से एकजुटता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि सोमवार को होने वाला विधानसभा मार्च शांतिपूर्ण रहे। रांची पुलिस आज के विधानसभा मार्च के लिए पूरी तरह तैयार है। SP पारस राणा ने प्रदर्शनकारी छात्रों को भरोसा दिलाया कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह एक जन-आंदोलन बन गया है। 'युवा' शब्द को उल्टा करने पर 'वायु' बनता है - और 'वायु' को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि आप इस विधानसभा मार्च में छात्रों का दर्द देख सकते हैं। मेरी 9 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी, मैं एम्बुलेंस से यहाँ आया हूँ और स्ट्रेचर पर इस मार्च का हिस्सा बना हूँ। लेकिन यह सरकार हमारी आवाज़ दबा रही है और वॉटर कैनन व आँसू गैस के गोले इस्तेमाल कर रही है। यह निंदनीय है। सरकार डरी हुई है, यह कायर सरकार है। सरकार जब-जब डरती है, तब-तब पुलिस को आगे करती है... हम आगे बढ़ते रहेंगे। सरकार के साथ हमारी 3 दौर की बातचीत हुई है, उन्हें हमारी माँगें पूरी करनी चाहिए। अगर छात्रों की माँगें पूरी नहीं हुईं, तो CM पद खतरे में पड़ जाएगा। सरकार हिल जाएगी, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह एक जन-आंदोलन बन गया है। 'युवा' शब्द को उल्टा करने पर 'वायु' बनता है - और 'वायु' को कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले रांची पुलिस ने विधानसभा की ओर बढ़ रहे JPSC-JSSC के प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।

संसद गतिरोध खत्म करने की पहल

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देने को तैयार अमित शाह

संसद के मानसून सत्र में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर जारी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को विपक्ष को चर्चा का रास्ता सुझाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष की चिंताओं का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार छात्रों के आंदोलन और 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि अगर वह गृह मंत्री का जवाब सुनना चाहता है, तो उसे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चर्चा और जवाब को लेकर कोई हिचक नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर विस्तार से अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं। दरअसल, अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के सांसद गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान की मांग कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर मानसून सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला है और कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। सोमवार को दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही दो बार स्थगन के बाद शुरू हुई। इस दौरान रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी शुरुआत से ही गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार की ओर से स्पष्ट किया कि गृह मंत्री छात्रों के मामले पर चर्चा और विस्तृत जवाब देने को तैयार हैं।

रेणुका चौधरी का सरकार पर तंज

'मोदिया बिंद' चश्मा दिखाकर अंधभक्तों पर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने सोमवार को केंद्र सरकार और उसके समर्थकों पर तीखा हमला बोला। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने 'मोदिया बिंद' नाम का स्टिकर लगा चश्मा दिखाया और इसे उन राजनीतिक समर्थकों के लिए 'इलाज' बताया, जिन्हें वह सरकार का अंधसमर्थक मानती हैं। चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार की आलोचना करने के बजाय कुछ लोग हर मुद्दे पर सिर्फ उसकी तारीफ करने में लगे रहते हैं।रेणुका चौधरी ने कहा कि ऐसे लोगों को देश में होने वाली कई महत्वपूर्ण घटनाएं दिखाई नहीं देतीं। उन्होंने बुनियादी ढांचे से जुड़े मामलों, कथित चोरी, NEET परीक्षा से जुड़े विवाद और अन्य जनहित के मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार के समर्थकों पर निशाना साधा। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि अगर किसी को 'मोतियाबिंद' जैसी समस्या है तो उसका भी इलाज कराया जाएगा। कांग्रेस सांसद का यह बयान ऐसे समय आया है, जब संसद के मानसून सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच सरकार की ओर से चार अहम विधेयक पेश किए गए। इनमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026, माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026, केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 शामिल हैं। हालांकि, विपक्षी सांसदों के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक स्थगित करना पड़ा। विपक्षी दल जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित चोरी के मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग कर रहे हैं।

24 हजार परिवारों के दावों की जांच के आदेश

मणिपुर हिंसा पीड़ितों को राहत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

मणिपुर में 2023 की जातीय हिंसा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने अपनी ओर से गठित तीन सदस्यीय कमिटी को उन दावों की जांच करने का निर्देश दिया, जिनमें कहा गया है कि हिंसा से प्रभावित करीब 24 हजार परिवारों को अब तक सरकारी पुनर्वास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है।चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस समेत कई वकीलों ने अदालत को बताया कि बड़ी संख्या में प्रभावित आदिवासी परिवार अभी भी सरकारी सहायता और पुनर्वास योजनाओं से वंचित हैं।कोर्ट ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर भी गौर किया। अदालत को बताया गया कि घर बनाने के लिए करीब 7 हजार लाभार्थियों की पहचान की गई थी, जिनमें से 4 हजार से अधिक लोगों को फंड जारी किया जा चुका है। सरकारी योजना के तहत कच्चे मकान के लिए 5 लाख रुपये और सेमी-पक्का या पक्का मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल कमिटी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्त मखीजा की दलीलों पर भी ध्यान दिया। कोर्ट को बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत हिंसा प्रभावित परिवारों के लिए 12 हजार से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा अस्थायी शेल्टर बनाए गए हैं और पक्के मकानों के लिए चिन्हित 885 लाभार्थियों को करीब 51.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अदालत ने कहा कि जिन परिवारों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें प्रति परिवार एक लाख रुपये की सहायता भी दी गई है। हालांकि, करीब 24 हजार परिवारों के लाभ से वंचित होने के दावे को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने कमिटी से जमीनी स्तर पर इसकी पुष्टि करने को कहा।

वंदे मातरम् को पूरा गाने के निर्देश ने केरल में बड़ा राजनीतिक विवाद

वंदे मातरम् को पूरा गाने के निर्देश ने केरल में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इससे VD सतीशन की सरकार पर विपक्ष और उसके अपने राजनीतिक सहयोगियों, दोनों की तरफ से दबाव बढ़ गया है। सामने आई जानकारी के अनुसार, इस विवाद के केंद्र में 6 अगस्त को जारी किया गया केरल के मुख्य सचिव विश्वनाथ सिन्हा का एक सर्कुलर है, जिसमें आजादी के दिन से जुड़े कार्यक्रमों के तहत 'वंदे मातरम' को "पूरा" गाने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक मुश्किल राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी है। यह उस राज्य की बात है जहां कांग्रेस और CPI(M) दोनों ही पारंपरिक रूप से सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम्' के पूरे संस्करण को गाने का विरोध करते रहे हैं। CPI(M) ने इस सर्कुलर को मुद्दा बनाते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि वह संघ परिवार के राजनीतिक एजेंडे के आगे झुक गई है। विपक्ष के नेता पिनराई विजयन ने इस मामले में सरकार पर तीखा हमला किया और सवाल उठाया कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार ने ऐसा आदेश क्यों जारी किया।

पंजाब में आतंकी साजिश नाकाम

ISI समर्थित BKI मॉड्यूल का भंडाफोड़, हैंड ग्रेनेड के साथ मुख्य सदस्य गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ISI समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के कथित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। काउंटर-इंटेलिजेंस जालंधर और SBS नगर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मॉड्यूल के एक मुख्य सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से एक 86-P हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ, जिससे एक संभावित हमले को नाकाम करने में सफलता मिली।पंजाब पुलिस के DGP के अनुसार, यह मॉड्यूल विदेश में बैठे कथित हैंडलर्स के निर्देश पर संचालित किया जा रहा था। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई सीमा पार से संचालित होने वाले आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक अहम सफलता है।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने विदेश में मौजूद हैंडलर्स के निर्देश पर जालंधर के आदमपुर के पास एक डेड लेटर बॉक्स यानी DLB से ग्रेनेड हासिल किया था। डेड लेटर बॉक्स एक गुप्त माध्यम होता है, जिसका इस्तेमाल आमने-सामने संपर्क किए बिना संदेश या सामान पहुंचाने के लिए किया जाता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, ऐसे माध्यमों के जरिए हथियार, पैसे या निर्देश एक स्थान पर छोड़े और दूसरे व्यक्ति द्वारा हासिल किए जा सकते हैं।पुलिस के मुताबिक, इस मामले में SBS नगर के सदर नवांशहर थाने में भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। अब जांच का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस कथित विदेशी हैंडलर्स की पहचान करने और मॉड्यूल से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि गिरफ्तार आरोपी को ग्रेनेड किसने उपलब्ध कराया और इसके पीछे स्थानीय स्तर पर कौन-कौन लोग मदद कर रहे थे। पुलिस इस मॉड्यूल के संभावित स्थानीय सपोर्ट नेटवर्क और विदेश में बैठे कथित संचालकों के बीच संपर्क की भी जांच कर रही है।पंजाब पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार से संचालित होने वाले आतंकी नेटवर्क और उनके स्थानीय संपर्कों पर निगरानी और मजबूत कर रही हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध फिर हुआ तेज

रातभर मिसाइल और ड्रोन हमलों से दोनों देशों में भारी नुकसान

रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे के इलाकों में रातभर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिसमें कई लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल हुए।यूक्रेन के खार्किव और ओडेसा समेत कई इलाकों को रूसी हमलों ने निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में जवाबी ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के सामने एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट इंटरसेप्टर की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है, वहीं दोनों देशों के बीच हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर भीषण युद्ध छिड़ गया है। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर रातभर बमबारी की। इसमें दोनों देशों के कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के शहरों में रूस रोजाना बड़े हमले कर रहा है। इससे यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के पास अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम एकमात्र एयर डिफेंस है, लेकिन इसके इंटरसेप्टर की भारी कमी होने के कारण यूक्रेन रूसी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा है। हालांकि, यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई में रूस को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमला किया। इससे बेलगोरोड में पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं, दो दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें एक 4 साल का लड़का भी शामिल है। वहीं, यूक्रेन के खार्किव में एक ऊंची बिल्डिंग वाले अपार्टमेंट ब्लॉक पर रूसी मिसाइलों से हमला हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट ओडेसा में दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन के हमले में आठ लोग घायल हो गए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की कई महीनों से अमेरिका और अन्य देशों से पैट्रियट सिस्टम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है। हालांकि, अमेरिका खुद ईरान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और वहां पैट्रियट सिस्टम की कमी हो गई है। जेलेंस्की यूक्रेन के अंदर पैट्रियट सिस्टम बनाने की अनुमति चाहते हैं या एलन मस्क से अपने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके रूस के अंदर हमलों को गाइड करने की मंज़ूरी लेना चाहते हैं, जो उसके मिसाइल लॉन्चर को मार गिरा सकते हैं। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, देशअधिकारियों ने कहा कि गिरते मलबे से एक व्यक्ति घायल हो गया, दो प्राइवेट घरों को नुकसान पहुंचा और एक अपार्टमेंट ब्लॉक की खिड़की उड़ गई। के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर, वाइल्डबेरीज और रूस के अंदर दूसरे टारगेट पर यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन से हमला कर रहा है। इससे रूस में फ्यूल का संकट पैदा हो गया है। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने रविवार को दावा किया कि रात भर में खार्किव इलाके में ड्रोन वेयरहाउस, ओडेसा पोर्ट पर यूक्रेन की सेना के फ्यूल डिपो और दूसरे सामान के स्टोर शामिल थे। रूस ने रात में 153 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। रूस के बेलगोरोड इलाके के अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 29 अपार्टमेंट ब्लॉक और पांच प्राइवेट घरों के साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और अनजान "कमर्शियल जगहों" को नुकसान पहुंचा है। मेयर एंड्री क्रावचेंको ने रविवार को कहा कि यूक्रेन के ड्रोन का मलबा रूस के शहर नोवोरोस्सियस्क में दो कंपनियों और एक प्राइवेट घर पर भी गिरा।

एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल रूस का दौरा कर सकते हैं

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

'पोलिटिको' की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन युद्ध को लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच F B I डायरेक्टर काश पटेल रूस जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक काश पटेल अक्टूबर के बीच में रूस की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। F B I चीफ की इस संभावित यात्रा को 'असामान्य और संवेदनशील' बताया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि काश पटेल का रूस से जुड़ी विवादित घटनाओं में शामिल रहने का इतिहास रहा है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल से शुरू हुआ था। इनमें उन जांचों पर शक पैदा करने की कोशिशें भी शामिल हैं, जिनमें यह पता लगाया जा रहा था कि क्या ट्रंप ने 2016 में अपनी चुनावी जीत के लिए रूस के साथ मिलीभगत की थी। इसके अलावा, 'पोलिटिको' के अनुसार, ब्यूरो के प्रमुख के तौर पर काश पटेल हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस की कड़ी नजर है।इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, रूस के सरकारी अखबार 'मोस्कोव्स्की कोम्सोमोलेट्स' ने कहा कि अगर FBI डायरेक्टर मदद चाहते हैं तो उन्हें कुछ ठोस प्रस्ताव साथ लाने चाहिए। रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज के अर्बातोव इंस्टीट्यूट फॉर US एंड कैनेडियन स्टडीज़ के व्लादिमीर वासिलीव ने अखबार से बातचीत में कहा, "माना जाता है कि रूस के पास डेमोक्रेट्स के बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है, और हम इसे किसी न किसी रूप में अमेरिकी पक्ष को दे सकते हैं।" उन्होंने इस यात्रा के संभावित मकसद पर अपनी राय रखी।वासिलिएव के 'रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल' के साथ करीबी संबंध हैं। इस संस्था की देखरेख रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करते हैं, जो इसके बोर्ड के चेयरमैन हैं। वासिलिएव ने आगे कहा, "साथ ही, अमेरिकियों के पास भी शायद कुछ बताने के लिए हो, क्योंकि रूसी पक्ष पूछ सकता है कि 'बदले में हमें क्या मिलेगा?' या यह पूछ सकता है कि 'इस या उस मुद्दे पर आपका क्या कहना है?'"

अंतरिक्ष में भी लहराया तिरंगा

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर मौजूद रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने भारतीय तिरंगे और अंतरिक्ष खोज के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का जश्न मनाने वाले संदेश के साथ इस मौके को मनाया। भारत के अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी के बीच, अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत और रूस के बीच सहयोग के इतिहास, खासकर अंतरिक्ष मिशन और मानव अंतरिक्ष उड़ान में उनकी दशकों पुरानी साझेदारी पर चर्चा की। कॉस्मोनॉट प्योत्र दुब्रोव ने भारतीय लोगों को शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं देते हुए कहा प्रिय दोस्तों, आज भारत गणराज्य अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दुब्रोव ने आगे कहा भारत औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ और आत्मनिर्भरता और समृद्धि के रास्ते पर चल पड़ा। इस संदेश में भारत के स्वतंत्रता दिवस और अंतरिक्ष के इतिहास की एक और अहम घटना के बीच संबंध पर भी ज़ोर दिया गया। इस साल सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन के अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बनने की घटना को 65 साल पूरे हो रहे हैं। नवंबर 1961 में गागरिन की भारत यात्रा ने सोवियत संघ और भारत के बीच के संबंधों को और मज़बूत किया। इस यात्रा के दौरान, वे दोनों देशों के बीच पनप रही दोस्ती का एक अहम प्रतीक बन गए। भारत के बारे में गागरिन के विचारों को याद करते हुए, अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष से देखने पर यह देश सुंदर लगता है, लेकिन धरती पर यह और भी सुंदर है क्योंकि यहाँ सच्चे दोस्त रहते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और रूस का सहयोग कई दशकों से चल रहा है। 1975 में, सोवियत संघ ने भारत का पहला उपग्रह 'आर्यभट्ट' लॉन्च किया, जो इस साझेदारी में एक अहम शुरुआती उपलब्धि थी। इसके लगभग एक दशक बाद, 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने, जब उन्होंने सोवियत सोयुज T-11 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी। कॉस्मोनॉट अन्ना किकिना के अनुसार, भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के ज़रिए यह साझेदारी लगातार आगे बढ़ रही है।

होर्मुज में बढ़ा तनाव, ईरान की नाकेबंदी के लिए अमेरिका ने तैनात किए 20 से ज्यादा युद्धपोत

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

होर्मुज जलडमरूमध्य पर तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नाकेबंदी तेज कर दी है। अमेरिका के 20 से ज्यादा युद्धपोत मिडिल ईस्ट में सैन्य मिशनों के लिए तैनात किए हैं। US सेंट्रल कमांड ने बताया कि इन मिशनों में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी को सख्ती से लागू करना शामिल है। यह तैनाती होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते तनाव के बीच की गई है। सेंट्रल कमांड ने बताया कि 9 अगस्त तक सेंट्रल कमांड ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने वाले 55 कमर्शियल जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया है। 2 जहाजों को हमला करके बेकार किया गया है, जबकि दो जहाजों पर चढ़कर जांच की गई है। अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती ऐसे समय में हुई है, जब ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरूमध्य में एक नए शिपिंग रूट पर समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को कहा कि जलमडरूमध्य में शिपिंग रूप के लिए ओमान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि समझौते का मतलब यह नहीं होगा कि होर्मुज खुल जाएगी।अराघची ने कहा कि होर्मुज तब तक नहीं खुलेगा, जब तक अमेरिका को पिछले द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघनों को ठीक नहीं करता है। एक दिन पहले ही ईरान ने होर्मुज खोलने के लिए नई शर्तें रखी हैं, जिसमें अमेरिका से अरबों डॉलर का मुआवजा, क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी, ईरान की नाकेबंदी और प्रतिबंध खत्म करने के साथ ही ईरानी संपत्तियों को बहाल करना शामिल हैं। इन मांगों ने अमेरिका के लिए शांति की कोशिश को बहुत मुश्किल बना दिया है। हालांकि, एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि जब कमर्शियल शिपिंग बहाल करने को लेकर समझौता हो जाएगा, तो ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी हटा ली जाएगी।

उच्चायुक्त ने PM तारिक रहमान से की मुलाकात

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

5 अगस्त को नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वर्चुअल संबोधन के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच राजनयिक तनाव के माहौल में, बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने सोमवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। यह एक महत्वपूर्ण राजनयिक बैठक थी। यह बैठक रविवार को त्रिवेदी और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के बीच हुई आमने-सामने की बातचीत के एक दिन बाद हो रही है; रहमान आज की बैठक में भी मौजूद थे। हाई कमिश्नर और विदेश मंत्री के बीच यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि हाल ही में भारत से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सार्वजनिक बयानों को लेकर ढाका और नई दिल्ली के बीच राजनयिक तनाव देखा गया है। यह राजनयिक बातचीत 5 अगस्त को नई दिल्ली में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वर्चुअल प्रेस इंटरेक्शन के बाद हो रही है। यह तारीख 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद उनके सत्ता से हटने की दूसरी बरसी थी, जिस पर ढाका ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। अपने संबोधन में हसीना ने कहा कि लोकतंत्र को बहाल करके देश को "सही राह" पर लाने के लिए वह दिसंबर में अपने देश लौटने के अपने संकल्प पर अडिग हैं, हालांकि उन्होंने वापसी पर कारावास या मृत्युदंड के खतरे को भी स्वीकार किया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इन बयानों का कड़ा विरोध दर्ज कराया और इनकी निंदा की। मंत्रालय ने कहा कि इस घटना से जनभावना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई है। रविवार को ढाका में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में बच्चों के लिए एक कोने का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, त्रिवेदी ने तारिक रहमान के साथ अपनी मुलाक़ात को लेकर उम्मीद जताई और दोनों देशों के नेताओं के बीच सीधी बातचीत के महत्व पर ज़ोर दिया। भारतीय राजदूत ने कहा कि मुझे लगता है कि जब दो नेता मिलते हैं, तो कई समस्याएं हल हो जाती हैं। जब हम एक-दूसरे से बात करते हैं, तो समस्याएं सुलझ जाती हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग साथ हैं और समाधान ज़रूर निकलेगा... यह ज़रूर होगा। मुझे पूरा यकीन है। यहां कुछ भी नकारात्मक नहीं है; सब कुछ सकारात्मक है।

संपादक की कलम से

देश की राजनीति इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भरोसे की कमी लगातार गहरी होती दिखाई दे रही है। संसद का मानसून सत्र अपने अंतिम दौर में है, लेकिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बजाय गतिरोध ज्यादा नजर आ रहा है। विपक्ष गृह मंत्री के बयान और छात्रों से जुड़े आंदोलन पर जवाब की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि वह इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और विपक्ष के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन जब दोनों पक्ष अपनी-अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को सदन की कार्यवाही से ऊपर रखने लगें, तो नुकसान लोकतांत्रिक व्यवस्था का होता है। संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाने और जनता के मुद्दों पर गंभीर बहस का सबसे बड़ा मंच है।इस समय परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव भी राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। इन मुद्दों का असर आने वाले वर्षों की चुनावी राजनीति और राज्यों के प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है। ऐसे में इन पर जल्दबाजी के बजाय व्यापक राजनीतिक सहमति और राज्यों की चिंताओं पर खुली चर्चा जरूरी है। खासकर दक्षिणी राज्यों की आशंकाओं को नजरअंदाज करना भविष्य में राजनीतिक तनाव को बढ़ा सकता है।इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनसीपी के शरद पवार गुट के सांसदों की मुलाकात ने भी सियासी अटकलों को हवा दी है। बैठक को विकास से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित बताया गया है, लेकिन परिसीमन को लेकर संभावित राजनीतिक समीकरणों की चर्चा ने महाराष्ट्र की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है। हालांकि, किसी भी राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक रुख का इंतजार जरूरी है।आज जरूरत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ाने की नहीं, बल्कि संवाद का रास्ता खोलने की है। सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए और विपक्ष को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विरोध की राजनीति संसद को ठप करने की राजनीति न बन जाए। जनता ने प्रतिनिधियों को बहस, सवाल और समाधान के लिए चुना है।सियासत में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन लोकतंत्र की ताकत इस बात में है कि मतभेदों के बावजूद संवाद जारी रहे। संसद चलेगी, तभी सवाल उठेंगे; सवाल उठेंगे, तभी जवाब मिलेंगे और जवाब मिलेंगे, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा।

PM मोदी से मिले शरद पवार गुट के 8 सांसद समर्थन की अटकलों से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत

पीएम मोदी से शरद पवार गुट के सभी 8 सांसदों की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की सियासत में अटकलें तेज हो गई हैं।बैठक में विकास और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन परिसीमन बिल को लेकर संभावित समर्थन ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है।हालांकि, सुप्रिया सुले ने इसे महाराष्ट्र के विकास से जुड़ी बैठक बताया है और किसी राजनीतिक समझौते के संकेत से इनकार किया है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

इंडी अलायंस के बड़े सहयोगी और शरद पवार की पार्टी के सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। NCP शरद पवार गुट की नेता और सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पार्टी के सभी आठ सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ सांसदों की करीब 15 से 20 मिनट तक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात में सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने रखे। बीड से सांसद बजरंग सोनवणे ने सोलापुर के उजनी डैम से बीड जिले को पानी उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं, शिरूर से सांसद अमोल कोल्हे ने नासिक-पुणे रेलवे लाइन को लेकर चल रहे विवाद का मुद्दा उठाया। भिवंडी से सांसद बालू मामा म्हात्रे ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम भूमिपुत्र दी बा पाटिल के नाम पर रखने की मांग की। किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई। हालांकि, इस मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा परिसीमन बिल को लेकर हो रही है। सियासी अटकलें हैं कि एनसीपी शरद पवार गुट के सभी आठ सांसद परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे सकते हैं। हालांकि, पार्टी की तरफ से इस पर अभी कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। शरद पवार की पार्टी के पास 8 सांसद हैं ऐसे में इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें भी तेज हो गई है क्योंकि इससे पहले 22 जुलाई को भी शरद पवार और सुप्रिया सुले, पीएम मोदी से मिल चुके हैं। अब NCP शरद पवार के सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई। शरद पवार की पार्टी के पास 8 सांसद हैं ऐसे में इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें भी तेज हो गई है क्योंकि इससे पहले 22 जुलाई को भी शरद पवार और सुप्रिया सुले, पीएम मोदी से मिल चुके हैं। अब NCP शरद पवार के सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई। हालांकि सुप्रिया सुले का कहना है कि ये मुलाकात महाराष्ट्र की विकास योजनाओं को लेकर थी। साथ ही ये भी साफ किया है कि उनकी पार्टी FCRA बिल का विरोध करेगी। वहीं, इस मुलाकात को लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। हर कोई कयास लगा रहा है कि शरद गुट महाराष्ट्र में कोई खेल कर सकता है, जिससे महाविकास आघाड़ी (MVA) को बड़ा झटका लग सकता है। महाराष्ट्र बीजेपी नेत्री नवनीत राणा इस मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर शरद पवार के सांसद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मीडिया से बातचीत में नवनीत राणा ने कहा, "महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर शरद पवार जी के सांसद मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो महाराष्ट्र की और प्रगति के बारे में सोच रहे हैं और इस सोच के साथ पीएम मोदी से मिल रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।"फिलहाल शरद पवार गुट के सांसदों की पीएम मोदी से होने वाली मुलाकात को लेकर तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि इन अटकलों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है।

छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा को तैयार मोदी सरकार, गृह मंत्री के बयान पर विपक्ष ने मांगी स्पष्टता

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

छात्रों के आंदोलन और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर संसद में सियासत तेज हो गई है। सोमवार को केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वह इस पूरे मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार छात्रों के आंदोलन और उससे जुड़ी घटनाओं पर पूरी और विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष से अपील की कि चर्चा के दौरान गृह मंत्री के बयान और सरकार के जवाब को बिना किसी व्यवधान के सुना जाए। उन्होंने कहा कि अगर इस विषय पर चर्चा शुरू होती है तो सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और सरकार के जवाब को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए।दरअसल, 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में संसद चलो मार्च का आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पैलेट गन के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया था। इस घटना के बाद मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया और विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया।विपक्ष की मांग रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर इस पूरे मामले पर बयान दें और छात्रों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करें।वहीं, गृह मंत्री के संसद में जवाब देने की बात पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी गृह मंत्री के बयान को नहीं देखा है, लेकिन विपक्ष की बैठकों में हुई चर्चा के मुताबिक मुख्य मुद्दा छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई और कथित बर्बरता पर सरकार का जवाब है।गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि गृह मंत्री पुलिस कार्रवाई और कथित बर्बरता के मुद्दे पर विस्तार से बोलेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस संबंध में अब तक पर्याप्त स्पष्टता नहीं आई है।विपक्ष ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों को भी संसद में उठाने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर भी चर्चा के लिए अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत

आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की मिली इजाजत

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने टीएमसी सांसद को इलाज के लिए तीन सप्ताह तक विदेश जाने की अनुमति दे दी। बनर्जी सितंबर में आंखों का इलाज कराने के लिए विदेश जा सकेंगे। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने और अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। यह तय करना अदालत का काम नहीं है कि किसी व्यक्ति को कहां इलाज कराना चाहिए। कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा से पहले अपनी यात्रा की पूरी जानकारी, फ्लाइट डिटेल्स, विदेश में ठहरने की जगह और संबंधित डॉक्टर व अस्पताल की जानकारी देने का निर्देश दिया है। बता दें कि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। वह 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर डराने-धमकाने वाले बयान देने से जुड़े एक पुलिस मामले का सामना कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को अभिषेक बनर्जी की विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की तत्काल अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा था कि जब भारत में ही इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत नजर नहीं आती। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलाज कहां कराया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिले। अभिषेक बनर्जी की ओर से विदेश जाकर इलाज की अनुमति के लिए दायर याचिका को हाई कोर्ट ने इससे पहले 20 जुलाई को भी खारिज कर दिया था। दरअसल, अभिषेक बनर्जी की आंख में 2016 में हुए एक सड़क हादसे के दौरान चोट लगी थी। इसी के बाद से उनकी आंख से जुड़ी समस्या का इलाज चल रहा है। अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने का बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि अगर उन्हें विदेश जाने दिया गया तो वह देश से बाहर रह सकते हैं।अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने का बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि अगर उन्हें विदेश जाने दिया गया तो वह देश से बाहर रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी अपनी मेडिकल स्थिति को विदेश जाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें इलाज की जरूरत है तो राज्य सरकार के अस्पताल में भी बेहतर

चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि वह अपने राजनयिक पासपोर्ट का इस्तेमाल भारतीय कानून से बचने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे देश में पहुंच जाता है, जिसके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो उसे वापस भारत लाना मुश्किल हो सकता है।

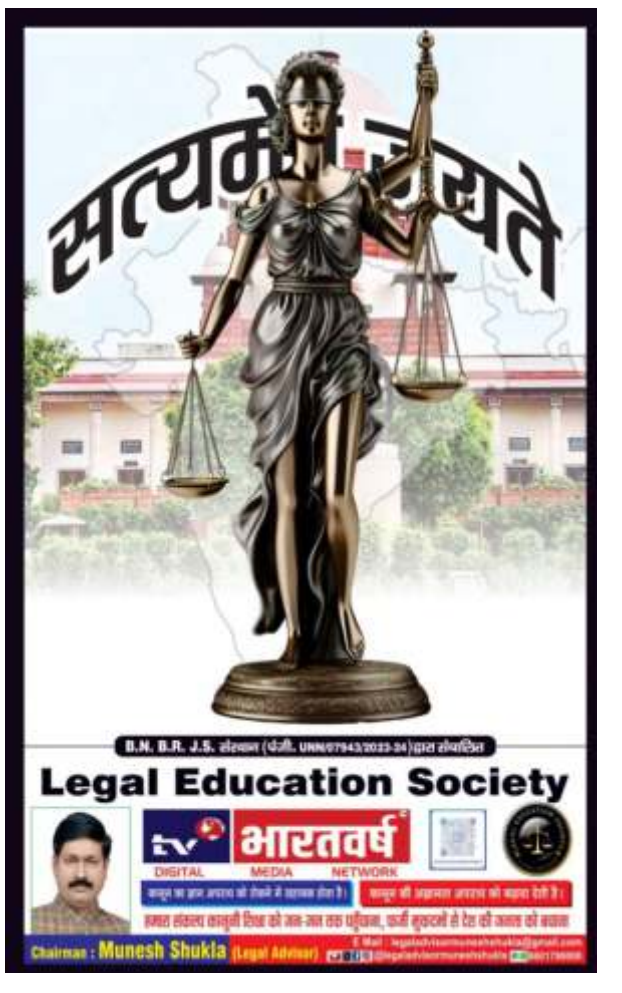

ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का सपना होगा आसान भारतीय छात्रों के लिए लॉन्च हुआ AAERI Verify

ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के इच्छुक भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। अब यहां की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना आसान होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय (MeiTY) के तहत आने वाले नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने AAERI Verify लॉन्च करने के लिए भारत में 'एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया' (AAERI) के साथ पार्टनरशिप की है।डिजिलॉकर से सीधे जुड़े इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से, ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने वाले छात्र अपने अकेडमिक, आइडेंटिटी और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का सुरक्षित, पेपरलेस और सहमति-आधारित वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। MeitY ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि इस प्लेटफॉर्म को दिल्ली में AAERI के सालाना सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। डिजिलॉकर पर वैसे भी स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते आए हैं। AAERI ने NeGD के साथ मिलकर AAERI Verify लॉन्च किया है। यह एक ऐसा ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म है जो ऑस्ट्रेलिया के हायर एजुकेशन संस्थानों के लिए छात्रों के क्रेडेंशियल की जांच की प्रक्रिया को आसान बनाता है। AAERI Verify प्लेटफॉर्म के साथ डिजिलॉकर को जोड़ने से, छात्र भरोसेमंद सोर्स से सीधे असली और जारीकर्ता द्वारा वेरिफाई किए गए डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित रूप से शेयर कर सकते हैं। इससे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और मैन्युअल वेरिफिकेशन प्रोसेस पर निर्भरता कम होती है।कागजी कार्रवाई और टाइम की बचत: अब स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लंबे और धीमे मैन्युअल प्रोसेस से नहीं गुजरना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कागजी कार्रवाई तुरंत और आसानी से हो जाएगी।

तेज एडमिशन प्रोसेस: इस प्लेटफॉर्म के आने से ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का प्रोसेस काफी तेज हो जाएगा, जिससे यूनिवर्सिटी के ऑफर्स और वीजा से जुड़े फैसले जल्दी मिलने में मदद मिलेगी।

सुरक्षित और फ्रॉड से बचाव: स्टूडेंट अपनी सहमति से सीधे ओरिजिनल अथॉरिटी से डिजिटल रूप से साइन डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकेंगे, जिससे फ्रॉड होने का जोखिम खत्म हो जाएगा।

फाइनेंशियल चेकिंग आसान: एडमिशन ऑफर मिलने के बाद स्पांसरशिप और फाइनेंस से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी इसी सुरक्षित डिजिटल फ्रेमवर्क के जरिए बिना किसी परेशानी के हो जाएगी।

डेटा प्राइवेसी: यह पूरी प्रक्रिया छात्रों की सहमति पर आधारित है, जिससे उनकी निजी जानकारी और दस्तावेजों की सुरक्षा पूरी तरह बनी रहती है॥T मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में शुरू किया गया डिजिटल वर्कफ्लो, धीरे-धीरे होने वाले मैनुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह एक सुरक्षित, दो-फेज वाले रणनीतिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। पहले चरण में, यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले ही स्टूडेंट की जांच आसानी से कर ली जाती है। इसके बाद दूसरा चरण आता है, जिसमें स्टूडेंट को एडमिशन का ऑफर मिलने के तुरंत बाद उसके फाइनेंशियल स्टेटस की जांच के लिए स्पांसरशिप जांच शुरू की जाती है। स्टूडेंट की मंजूरी से, डिजिलॉकर ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज को ओरिजिनल जारी करने वाले अधिकारियों से डिजिटल रूप से साइन रिकॉर्ड का सीधा एक्सेस देगा। मंत्रालय ने कहा कि इससे धोखाधड़ी का जोखिम खत्म हो जाता है, डेटा की पूरी गोपनीयता सुनिश्चित होती है और एप्लीकेशन प्रोसेस में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है।

सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत आईटीबीपी में मेडिकल ऑफिसर की रिक्तियां भरी जा रही

मेडिकल फील्ड से जुड़े कैंडिडेट्स जो देशसेवा करना चाहते है, उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकली है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) को मेडिकल ऑफिसर्स की जरूरत है। इस बल के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर सेलेक्शन बोर्ड के जरिए विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। हाल ही में इस भर्ती से जुड़ा आधिकारिक विज्ञापन आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लिकेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। आईटीबीपी ने ग्रुप -A सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स (सेकंड इन कमांड), स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स (डिप्टी कमांडेंट) और मेडिकल ऑफिसर्स (असिस्टेंट कमांडेंट) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लिकेशन विंडो अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 तक खुली रहेगी। आवेदन से पहले योग्यता और जरूरी डिटेल्स भी जान लें। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपनी 10वीं की मार्कशीट, योग्यता सर्टिफिकेट/डिग्री., इंटर्नशिप, NMC/MCI/ स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आदि सर्टिफिकेट ओरिजिनल और इनकी स्वप्रमाणित फोटोकॉपी साथ लेना जानी होंगी।

इसके बाद 200 नंबरों का साक्षात्कार होगा। जिसमें कैंडिडेट्स से जनरल नॉलेज, एकेडमिक स्टडी, जजमेंट, सोशल एबिलिटी आदि से सवाल पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के लिए 80 नंबर चाहिए होंगे।

अगले चरण में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) होगा। पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट 157.5 Cms और महिलाओं की 142 Cms होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की

तेज़ गेंदबाज़ भुवनेश्वर कुमार ने अपनी राय दी खुद को 'पूरी तरह तैयार' बताया

ODI वर्ल्ड कप 2027 शुरू होने से पहले ही वर्ल्ड क्रिकेट में चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। अगले साल होने वाले इस टूर्नामेंट को वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे अहम खिताब माना जाता है और इसके करीब आते ही अलग-अलग टीमें इसकी तैयारी में जुट गई हैं। टूर्नामेंट से पहले, भारतीय टीम के स्क्वाड को लेकर काफी चर्चा हो रही है और इसमें भुवनेश्वर कुमार के संभावित शामिल होने की बात भी एक अहम मुद्दा बनी हुई है॥PL के शानदार सीज़न के बाद, जिसमें उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरा IPL खिताब जिताने में मदद की, भुवनेश्वर कुमार हाल के समय में बेहतरीन फ़ॉर्म में रहे हैं। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स उन्हें भारतीय टीम में शामिल करने का समर्थन कर रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए, 36 वर्षीय खिलाड़ी ने खुद कहा है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह इसके लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने भुवनेश्वर कुमार के हवाले से कहा कि अगर मुझे बुलावा आता है तो मैं मना क्यों करूंगा? मैं पूरी तरह तैयार हूं। सच कहूं तो, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि मैं कितना तैयार हूं। मेरा काम क्रिकेट खेलना है और इसीलिए मैं यहां UP T20 लीग में खेलने आया हूं। मैं यहां किसी दूसरी जगह जाने या किसी दूसरे लेवल पर पहुंचने के इरादे से नहीं आया हूं। उन्होंने आगे कहा कि हम IPL यह जानते हुए खेलते हैं कि हमें टीम के लिए अच्छा खेलना है और मैच जीतने हैं, लेकिन मैं UP T20 लीग में इस उम्मीद से नहीं आया कि मुझे कहीं और चुना जाएगा या किसी के कुछ कहने की वजह से आया हूं। अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो, भले ही वे अभी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन एक समय वे टीम का अहम हिस्सा हुआ करते थे।

मिचेल मार्श द हंड्रेड 2026 में शानदार बल्लेबाजी कर रहे

इंग्लैंड में इन दिनों द हंड्रेड 2026 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में 9 अगस्त को सनराइजर्स लीड्स और वेल्श फायर के बीच मैच खेला गया, जिसमें लीड्स की टीम ने 71 रनों के बड़े अंतर से बड़ी जीत दर्ज की। सनराइजर्स लीड्स के लिए इस मैच में मिचेल मार्श ने मैच विनिंग पारी खेली। उन्होंने 34 बॉल पर 50 रन बनाए। अपनी इस पारी के दौरान मार्श ने टी20 क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 7 हजार रन पूरे किए। द हंड्रेड के इस सीजन में मिचेल मार्श शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।द हंड्रेड 2026 में मिचेल मार्श ने अब तक 7 मैच खेले हैं और वहां उन्होंने 7 पारियों में 53.42 के औसत से 374 रन बनाए हैं। मार्श फिलहाल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस सीजन 300 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो क्लार्क का नाम है, उन्होंने द हंड्रेड 2026 में बर्मिंघम फीनिक्स के लिए खेलते हुए 7 मैचों की 7 पारियों में 290 रन बनाए हैं। ट्रेंट रॉकेट्स के बेन डकेट इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 7 मैचों में 289 रन बनाए हैं। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के जॉस बटलर का नाम चौथे नंबर पर है। बटलर हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। 7 मैचों में उनके बल्ले से 278 रन आए हैं। सनराइजर्स लीड्स के ही रेयान रिकेलटन 7 मैचों में 274 रन बनाकर लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। सनराइजर्स लीड्स की टीम इस सीजन बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने इस सीजन अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 5 मैच में जीत मिली है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। 20 पॉइंट्स के साथ सनराइजर्स की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। वहीं पहले नंबर पर ट्रेंट रॉकेट्स की टीम टेबल में टॉप पर है।

जुलाई के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए 3 खिलाड़ियों में टक्कर

हर महीने दिए जाने वाले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के तहत जुलाई 2026 के लिए नामांकित किए गए खिलाड़ियों के नामों का खुलासा हो गया है। इस बार अवॉर्ड की रेस में तीन पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले महीने अपनी टीमों के लिए कमाल का प्रदर्शन किया है। इनमें सबसे पहला नाम वेस्टइंडीज के हरफनमौला जस्टिन ग्रीव्स का है। दूसरे इंग्लैंड व्हाइट बॉल टीम के कप्तान हैरी ब्रूक हैं, तो तीसरे बांग्लोदश बल्लेबाज तंजीद हसन हैं।जस्टिन ग्रीव्स ने जुलाई में वेस्टइंडीज के लिए शानदार हरफनमौला प्रदर्शन किया। नॉर्थ साउंड में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 180 रन बनाए, जिससे विंडीज ने श्रीलंका के स्कोर का मजबूती से जवाब दिया। उनके प्रदर्शन के दम पर ही मेजबान टीम टेस्ट ड्रॉ करने और सीरीज 1-0 से जीतने में कामयाब रही।ग्रीव्स ने महीने के आखिर में तारौबा में पाकिस्तान के खिलाफ गेंद से पहली पारी में 5/27 और दूसरी पारी में 2/12 के फिगर के साथ वेस्टइंडीज के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन किया। जुलाई में ग्रीव्स ने दो टेस्ट में 71.66 के औसत से 215 रन बनाए और सिर्फ 10.25 के औसत से आठ विकेट भी लिए। इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कप्तान हैरी ब्रूक के लिए पिछला महीना काफी शानदार रहा। उन्होंने भारत के खिलाफ अपनी टीम की व्हाइट-बॉल सफलता में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भले ही तीन वनडे में 31 रन बनाए, लेकिन टी20 इंटरनेशनल सीरीज में अपनी सबसे अच्छी फॉर्म दिखाई। उन्होंने इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर को मजबूत करते हुए पांच मैचों में 114.50 के औसत से 229 रन बनाए। ब्रूक की अगुवाई और बल्ले से आक्रामक रवैये के चलते इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ वनडे और टी20 दोनों सीरीज में जीत हासिल की। तंजीद हसन जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के दौरान बांग्लादेश के सबसे अच्छे बैट्समैन में से एक बनकर उभरे। उन्होंने जुलाई का अंत दोनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में किया। इस ओपनर ने वनडे सीरीज के तीन मैचों में 53.00 के और और 89.83 के स्ट्राइक रेट से 159 रन बनाए।

जापानी युवक का वीडियो वायरल

लाखों रूपए खर्च कर शख्स बना कुत्ता?

जापान के टोको नाम के शख्स की कुत्ते जैसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. दावा किया गया कि उसने कुत्ता बनने के लिए 220 करोड़ रुपये खर्च किए. हालांकि टोको ने करीब 20 लाख येन यानी 11-12 लाख रुपये खर्च किए थे.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीबोगरीब दावा तेजी से वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि जापान के एक करोड़पति ने खुद को कुत्ते जैसा दिखाने के लिए करीब 220 करोड़ रुपये खर्च कर दिए.

दावा है कि उसने कई तरह की सर्जरी और प्रक्रियाओं के जरिए अपना पूरा रूप बदल लिया. वीडियो और तस्वीरें देखने के बाद लोग भी हैरान हैं कि आखिर कोई इंसान कुत्ता बनने के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च करेगा. लेकिन इस वायरल दावे की कहानी कुछ अलग है.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में जो दिखाया गया है, उसे देखकर कई लोग इसे AI से बनाया गया वीडियो बता रहे हैं. हालांकि, वीडियो की सच्चाई को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक जापान के जिस शख्स की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे, उसका नाम टोको है. उसने खुद को कुत्ता बनाने के लिए कोई सर्जरी नहीं करवाई थी. बल्कि उसने एक बेहद खास और असली दिखने वाली कुत्ते की इेस तैयार करवाई थी. जापान के टोको को बचपन से ही जानवरों से खास लगाव था. उसका सपना था कि वह कुछ समय के लिए जानवरों जैसा जीवन महसूस करे. ⊙

आखिर कुत्ता ही क्यों बनना चाहता था?

यह वीडियो जुलाई 2023 में काफी वायरल हुआ था. टोको के मुताबिक उसे बचपन से ही जानवर पसंद थे. खास तौर पर उसे प्यारे और चार पैरों वाले जानवर आकर्षित करते थे. इसलिए उसने इंसान की जगह कुत्ते का रूप चुनने का फैसला किया. उसने बॉर्डर कॉली को इसलिए भी चुना क्योंकि इस नस्ल के कुत्तों के शरीर पर लंबे और घने बाल होते हैं. इससे इंसानी शरीर को कॉस्ट्यूम के अंदर छिपाना आसान हो जाता है और पूरा लुक ज्यादा असली दिखाई देता है. टोको की यह कहानी सिर्फ कुत्ते तक सीमित नहीं है. बाद की रिपोर्ट में उसने बताया था कि वह भविष्य में दूसरे जानवरों का रूप भी आजमाना चाहता है. ⊙

जलभराव पर महिला का तंज, नाव लेकर निकलना था

दिल्ली-एनसीआर में बारिश शुरू होते ही जलभराव की समस्या फिर सुर्खियों में आ गई है. पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम और दिल्ली की पानी से लबालब सड़कों के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. अब नोएडा का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने बारिश के बाद सड़क की हालत दिखाते हुए शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठाए हैं. वायरल वीडियो नोएडा के सेक्टर-18 का बताया जा रहा है. ⊙

ठेक की नौकरी छोड़ क्रिएटर बना कपल

35 लाख रुपये सालाना की टेक नौकरी छोड़ने वाले एक कपल का दावा है कि उन्होंने कंटेंट क्रिएशन से तीन साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में उन्होंने अपनी कमाई, ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग और दूसरे इनकम सोर्स का पूरा हिसाब बताया.

सोशल मीडिया पर अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई कितनी होती है. अब एक कपल ने इस सवाल का जवाब अपनी पूरी इनकम डिटेल्स के साथ दिया है.

टेक सेक्टर की लाखों रुपये की नौकरी छोड़ने वाले इस कपल का दावा है कि उन्होंने कंटेंट क्रिएशन से तीन साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. मुस्कान मित्तल और आशीष गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी टेक जॉब से लेकर फुल-टाइम कंटेंट क्रिएटर बनने तक का सफर बताया.

उनका कहना है कि पिछले तीन साल में हजारों लोगों ने उनसे पूछा कि वे ट्रैवल और कंटेंट क्रिएशन का खर्च कैसे उठाते हैं. इसी वजह से उन्होंने पहली बार अपनी कमाई का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया. वीडियो में आशीष गुप्ता ने बताया कि कंटेंट क्रिएशन शुरू करने से पहले वह डेटा एनालिस्ट थे और उनकी इन-हैंड सैलरी करीब 12 लाख रुपये सालाना थी.

वहीं मुस्कान मित्तल सॉफ्टवेयर डेवलपर थीं और उन्हें करीब 23 लाख रुपये सालाना मिलते थे. यानी दोनों की संयुक्त सालाना आय करीब 35 लाख रुपये थी. ऐसे हुई कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत कपल के मुताबिक, मई 2023 में उन्होंने ट्रैवल से जुड़े वीडियो बनाना शुरू किया. वियतनाम ट्रिप का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे 20 हजार से ज्यादा व्यूज मिले. इसके बाद उन्होंने नियमित रूप से ट्रैवल, रिलेशनशिप और हेल्थ से जुड़ा कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया. ⊙

वीडियो हो रहा वायरल

मुस्कान और आशीष का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई यूजर्स उनकी पारदर्शिता की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कंटेंट क्रिएशन में इतनी सफलता हर किसी को नहीं मिलती. फिलहाल, कपल की ओर से साझा किए गए इनकम के आंकड़ों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं हुआ है.

करीब एक दशक से चल रही कानूनी लड़ाई अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. अमेरिकी हेल्थकेयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन (जेएंडजे) ने घोषणा की है कि वह अपने बेबी पाउडर और अन्य टैल्क उत्पादों को लेकर दायर हजारों मुकदमों के निपटारे के लिए 5.5 अरब डॉलर (करीब 52 हजार करोड़ रुपये) का भुगतान करेगी. हालांकि, सबसे अहम बात यह है कि कंपनी ने यह नहीं माना है कि उसके टैल्क उत्पादों से कैंसर होता है. जेएंडजे का कहना है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं. ⊙

लोपामुद्रा राउत के घर 76 लाख की चोरी का खुलासा, बिहार से आरोपी गिरफ्तार

अभिनेत्री और पूर्व 'बिग बॉस' प्रतियोगी लोपामुद्रा राउत के मुंबई स्थित घर से करीब 76.39 लाख रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को दरभंगा से पकड़ा है। उसके पास से चोरी की गई करीब 51 लाख रुपये की संपत्ति बरामद होने का दावा किया गया है। मुंबई की सांताक्रूज पुलिस के मुताबिक, चोरी की यह वारदात जुलाई में मुंबई के सांताक्रूज स्थित लोपामुद्रा राउत के घर में हुई थी। आरोपी घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गया था। चोरी किए गए सामान में महंगी घड़ी, सोने के दो बिस्किट और नकदी समेत अन्य कीमती वस्तुएं शामिल थीं।मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी जानकारी और स्थानीय स्तर पर मिली सूचनाओं के आधार पर आरोपी की पहचान की। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को उसके बिहार में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद एक टीम दरभंगा पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 51 लाख रुपये से अधिक की चोरी की संपत्ति बरामद की है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी में उसके साथ कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं और बाकी रकम या सामान कहां है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने उस समय चोरी को अंजाम दिया, जब लोपामुद्रा काम के सिलसिले में शहर से बाहर थीं। एक्ट्रेस 20 जून से 27 जुलाई के बीच शहर से बाहर गई हुई थीं। इसी दौरान आरोपी ने चोरी का प्लान बनाया और उनके घर में रखे सोने के गहने, कैश और सोने के बिस्किट लेकर फरार हो गया। इसके बाद लोपामुद्रा ने मुंबई के सांताक्रूज पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर सांताक्रूज पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच ने जॉइंट ऑपरेशन के जरिए आरोपी को ढूंढ निकाला और उसके पास से बरामद लाखों का सामान जब्त कर लिया है। लोपामुद्रा राउत की बात करें तो वह एक एक्ट्रेस और ब्यूटी पेजेंट विनर हैं। लोपामुद्रा, तब सुर्खियों में आईं जब सलमान खान के शो 'बिग बॉस' में एंट्री ली। अलावा वह रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड शो के खिलाड़ी' में भी नजर आ चुकी हैं और वेब सीरीज में भी एक्ट्रेस ने काम किया पिछले कुछ समय से वह एक्टिंग में दा एक्टिव नहीं हैं, लेकिन अक्सर शल मीडिया पर अपने फैंस से जुड़ी ती हैं और पर्सनल-प्रोफेशनल इफ से जुड़े अपडेट्स शेयर करती रहती हैं। कुछ महीने पहले 'बिग बॉस' फेम कशिश कपूर के घर भी चोरी का मामला सामने आया था। एक्ट्रेस ने इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए पूरी घटना का जिक्र किया था। उन्होंने इसके 'खतरों कुछ है। ज्या सो रह ला

FCRA बिल पर सियासी संग्राम तेज
अखिलेश यादव ने केंद्र पर संस्थाओं को नियंत्रित करने का लगाया आरोप

FCRA संशोधन विधेयक 2026 को लेकर संसद से बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है।अखिलेश यादव ने केंद्र पर विदेशी फंडिंग के नाम पर संस्थाओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए भारतीय धन के विदेश जाने पर सवाल उठाए।वहीं, सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विदेशी चंदे से जुड़े नियमों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

एफसीआरए बील को लेकर संसद से बाहर भी सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भारतीय धन के विदेश जाने और विदेशी फंड पर लगने वाली पाबंदियों को लेकर सवाल उठाए हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि FCRA के जरिए संस्थाओं पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान अखिलेश यादव ने BJP को 'लैंड माफिया' पार्टी बताया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के नाम पर संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि देश का कितना पैसा विदेश जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि भारत का कितना पैसा विदेश जा रहा है। विदेश से पैसा लाने पर प्रतिबंध हैं, लेकिन भारतीय पैसा कितना बाहर जा रहा है, इस पर कोई रोक नहीं है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, अमीरों के अच्छे दिन आए हैं। बड़े लोग ही फल-फूल रहे हैं। सरकार उन पर प्रतिबंध कब लगाएगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अगर सरकार भारतीय धन के विदेश जाने पर रोक नहीं लगाती है तो इससे यह संदेश जाता है कि FCRA का इस्तेमाल केवल अल्पसंख्यकों को परेशान करने या आतंकवाद और आतंक के वित्तपोषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सच्च है कि बड़ी मात्रा में भारतीय पैसा विदेश जा चुका है।अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि FCRA के जरिए संस्थाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि लाठियां क्यों चलाई गईं, आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए और बिजली के झटके क्यों दिए गए। अब वे FCRA ला रहे हैं। जबकि भारत सरकार और बीजेपी ने हमें भरोसा दिलाया था कि भारत का पैसा देश से बाहर नहीं जाएगा। अनगिनत लोगों ने भारत से बड़ी रकम बाहर ले ली है, आधिकारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों से उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार की मंशा संस्थाओं को अपने नियंत्रण में लेने की है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 को मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में दोबारा पेश किया गया है। सरकार के अनुसार, इस विधेयक का उद्देश्य विदेश से मिलने वाले चंदे और आर्थिक मदद से जुड़े नियमों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। प्रस्तावित कानून में एक नामित प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है। यह प्राधिकरण उन संस्थाओं की विदेशी फंड से खरीदी गई संपत्तियों की निगरानी करेगा, जिनका एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो चुका है, समाप्त हो गया है या जिन्होंने अपना पंजीकरण वापस ले लिया है।

जन्माष्टमी से पहले उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने तीन दिन और दो रात का कृष्ण लीला टूर पैकेज शुरू किया

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं को ब्रज धाम की आध्यात्मिक यात्रा का विशेष उपहार दिया है। 'विजिट माय स्टेट उत्तर प्रदेश' अभियान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने तीन दिन और दो रात का 'कृष्ण लीला' टूर पैकेज शुरू किया है। यह विशेष पैकेज श्रद्धालुओं को मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना जैसे भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़े प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के दर्शन एक ही यात्रा में कराएगा। यात्रा का शुभारंभ लखनऊ से सुबह 08 बजे होगा। यह पैकेज आध्यात्मिक पर्यटन को नई उड़ान देने के साथ कृष्ण-ब्रज सर्किट को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'कृष्ण लीला' टूर पैकेज 'विजिट माय स्टेट उत्तर प्रदेश' अभियान की उस व्यापक सोच का साकार स्वरूप है, जिसके माध्यम से प्रदेश की धार्मिक पर्यटन विरासत को देश-विदेश के अधिकाधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह पहल कृष्ण-ब्रज सर्किट को मजबूती प्रदान करने के साथ श्रद्धालुओं को भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े स्थलों के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि 'ब्रज क्षेत्र की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाज़ा लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या से लगाया जा सकता है। वर्ष 2025 में मथुरा में 10.24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का आगमन हुआ, जबकि ब्रज रंगोत्सव-2025 में 44 लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता कर इस सांस्कृतिक महोत्सव को ऐतिहासिक बना दिया। वहीं वर्ष 2026 के पहले तीन महीनों में ही लगभग 1.90 करोड़ पर्यटकों के आगमन ने यह स्पष्ट किया कि ब्रज क्षेत्र देश के सबसे तेजी से उभरते आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित कर चुका है।'

राम मंदिर दान मामले पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला
बोले- छात्रों के साथ आस्था के मुद्दे पर भी हो चर्चा

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश राम मंदिर चोरी मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रुख अपनाया गया है। इस बीच संसद के मानसून सत्र के दौरान राम मंदिर दान चोरी मुद्दे पर बहस कराए जाने की मांग समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। पिछल दिनों पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में सपा सांसदों का समूह दान चोरी मुद्दे पर सदन के बाहर नाटक में भाग लेता दिखा। अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को राम मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा करानी चाहिए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार छात्रों का मुद्दा अहम है। उसी प्रकार से आस्था से खिलवाड़ का मुद्दा भी अहम है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और फैजाबाद-अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद दान चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान अखिलेश यादव के हाथों में 'दूध का दूध और पानी का पानी' लिखा पोस्टर था। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को पता है कि मानसून सत्र में दो दिनों का समय बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि जितना छात्र-नौजवानों का मसला, नीट का मसला, परीक्षाओं के पेपर लीक का मसला अहम है। उतना ही आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वह इंपोर्टेंट है। सरकार दोनों मामलों पर चर्चा करे, विपक्ष तैयार है। राम मंदिर मसले पर प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण के मसले पर

अखिलेश ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी हो गई। लोगों को जेल भेज दिया गया। इसके बाद भी सरकार क्यों नहीं सफाई देना चाहती है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अरे दूध का दूध पानी का पानी न करो, चांदी का चांदी और सोने का सोना तो वापस कर दो। हम चाहते हैं कि दोनों मुद्दों पर चर्चा हो। अब दो दिन समय बचा है, हम मांग करते रहेंगे। दरअसल, राम मंदिर के दान में दिए गए सोने और चांदी के आभूषणों की हेराफेरी का भी आरोप लगा है। इसी मसले पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। हालांकि, मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वीकृत एसआईटी के स्तर पर मामले की जांच चल रही है।

रक्षाबंधन से पहले सजा लखनऊ का चौक बाजार

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन इस वर्ष भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। त्योहार से पहले राजधानी लखनऊ का ऐतिहासिक चौक सर्राफा बाजार रंग-बिरंगी और आकर्षक चांदी की राखियों से पूरी तरह सज गया है। बाजार में इस बार पारंपरिक रोली-चावल वाली सिल्वर राखियों के साथ-साथ 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर, ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, एंटीक फिनिश, कुंदन, डायमंड लुक और धार्मिक प्रतीकों से सजी प्रीमियम राखियां ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही हैं। सुबह से देर रात तक खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और बाजार पूरी तरह रक्षाबंधन के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है।त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही सर्राफा बाजार में रौनक कई गुना बढ़ गई है। दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और विभिन्न डिजाइनों की हजारों राखियां ग्राहकों के लिए प्रदर्शित की गई हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों की राखियां पसंद कर रही हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी चांदी के उपहारों और पूजा सामग्री की खरीदारी में जुटे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस बार ग्राहकों का रुझान विशेष रूप से सिल्वर राखियों की ओर बढ़ा है। चौक सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री विनोद माहेश्वरी ने बताया कि इस वर्ष बाजार में धार्मिक भावनाओं से जुड़ी राखियों की विशेष मांग है। श्रीकृष्ण, ॐ, त्रिशूल, त्रिशूल विद रुद्राक्ष, जय श्री राम, रुद्राक्ष, नज़र बट्टू, इविल आई, मेरे भैया और वीरा जैसे आकर्षक डिजाइनों वाली चांदी की राखियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। उन्होंने बताया कि धार्मिक प्रतीकों के साथ आधुनिक फिनिश और आकर्षक पैकेजिंग ने इन राखियों को और भी खास बना दिया है।

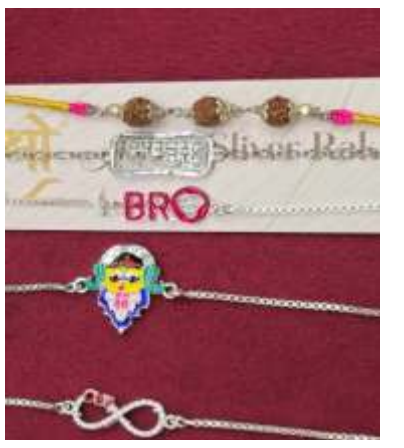

आईटीआई प्रवेश में विकल्प बदलने का मौका
5 अगस्त रात 12 बजे तक खुला रहेगा एससीवीटी पोर्टल

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के विशेष सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि प्रदेश के राजकीय-निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में संचालित व्यवसायों, टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 211 राजकीय संस्थानों में संचालित 10 दीर्घकालीन व्यवसायों एवं पीपीपी मॉडल पर संचालित राजकीय संस्थानों के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु विकल्प परिवर्तन (संस्थान/व्यवसाय) के लिए एससीवीटी पोर्टल खोला गया है। उन्होंने बताया कि सर्वसाधारण के लिए 09 से 12 अगस्त तक विकल्प परिवर्तन हेतु पोर्टल खोला गया है। साथ ही अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट http://www.scvtup.in पर नवीन ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण एवं विकल्प परिवर्तन (संस्थान/व्यवसाय) हेतु 15 अगस्त रात 12 बजे तक एससीवीटी पोर्टल खुला रहेगा। इसके बाद आवेदन, पंजीकरण, विकल्प परिवर्तन के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में सहायता हेतु विवरणी (दिशा-निर्देश) ई-फॉर्म में वेबसाइट www.scvtup.in पर उपलब्ध है।

सावन के दूसरे सोमवार पर शिवमय हुआ उन्नाव, गंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

सावन के दूसरे सोमवार को जिलेभर में आस्था और भक्ति का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही प्रमुख गंगा घाटों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों श्रद्धालुओं ने तड़के गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान घाटों से लेकर मंदिरों तक हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे गूंजते रहे।गंगाघाट, शुक्लागंज, बक्सर, फत्तेपुर समेत जिले के अन्य प्रमुख गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। गंगाघाट क्षेत्र में सबसे अधिक भीड़ रही। यहां तड़के करीब चार बजे से ही श्रद्धालु परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे थे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने गंगाजल भरा और भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए शिवालयों की ओर रवाना हुए। घाटों पर पूरे दिन धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा। सावन के सोमवार को कांवड़ियों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। डाक कांवड़, मोटरसाइकिल कांवड़ और पैदल कांवड़ लेकर श्रद्धालु विभिन्न शिवालयों की ओर जाते नजर आए। कई कांवड़िए रात से ही गंगा घाटों पर पहुंच गए थे। गंगा स्नान के बाद उन्होंने

पात्रों में जल भरा और शिवालयों की ओर प्रस्थान किया। कांवड़ियों की सेवा के लिए रास्ते में कई स्थानों पर भंडारे और जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। शहर के प्रसिद्ध गोकुल बाबा मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, फूल और गंगाजल अर्पित कर विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा की। मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। दूर-दराज से गंगा घाटों पर पहुंचे कांवड़ियों ने बताया कि सावन के सोमवार को गंगा स्नान कर भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करने की विशेष धार्मिक मान्यता है। इसी आस्था के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों से जल भरकर पैदल, मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों से शिवालयों की ओर रवाना हुए।सावन के दूसरे सोमवार पर जिलेभर में सुबह से देर शाम तक धार्मिक गतिविधियां जारी रहीं। गंगा घाटों और शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़ ने पूरे जिले को भक्तिमय बना दिया।

अराजकतत्वों ने खंडित की आंबेडकर प्रतिमा, गांव में बढ़ा आक्रोश

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र स्थित हसनापुर मजरा सतगुरु खेड़ा गांव में सोमवार सुबह डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी गई। अराजकतत्वों द्वारा की गई इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही सोहरामऊ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्थापित डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा को अराजकतत्वों ने क्षतिग्रस्त किया है। सुबह जब लोगों की नजर खंडित प्रतिमा पर पड़ी, तो उन्होंने इसकी जानकारी अन्य ग्रामीणों को दी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और घटना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि प्रतिमा को कब और कैसे क्षतिग्रस्त किया गया। घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। सोमवार को ही सीओ हसनगंज तेज बहादुर सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। सीओ ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और प्रतिमा खंडित करने वाले अराजकतत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्नाव समेत कई जिलों के यात्रियों को फायदा, दो एक्सप्रेस ट्रेनों का विलय

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए दो एक्सप्रेस ट्रेनों का विलय कर दिया है। सोमवार दोपहर को चित्रकूटधाम कर्वी-कानपुर सेंट्रल और मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस के विलय को मंजूरी मिली है। इस विलय के बाद अब यह संयुक्त सेवा 14123/14124 मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-चित्रकूटधाम कर्वी एक्सप्रेस के रूप में संचालित होगी। इस नई व्यवस्था से प्रतापगढ़ और चित्रकूट के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध हो जाएगी। रेलवे ने इस संयुक्त ट्रेन में कोचों की संख्या भी बढ़ाई है। पहले दोनों सेवाओं में कुल 12 कोच थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 24 कोच किया जाएगा। इससे यात्रियों को अधिक सीटें मिलेंगी और ट्रेन की वहन क्षमता भी बढ़ेगी। नई संयुक्त सेवा से प्रतापगढ़ और चित्रकूटधाम के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को कानपुर में ट्रेन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनका सफर और सुविधाजनक बनेगा। यह ट्रेन मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ से शुरू होकर अमेठी, गौरीगंज, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर सेंट्रल, घाटमपुर, हमीरपुर रोड, बांदा और अतर्रा होते हुए चित्रकूटधाम कर्वी तक पहुंचेगी। वापसी में भी यह ट्रेन इसी मार्ग पर यात्रा कराएगी। इससे इन सभी प्रमुख स्टेशनों से जुड़े यात्रियों को एक ही ट्रेन के माध्यम से लंबी दूरी की यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्नाव के यात्रियों के लिए भी यह नई सेवा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली और चित्रकूट की ओर जाने वाले यात्रियों को अब बेहतर रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। विशेष रूप से, धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी इस ट्रेन सेवा से सीधा लाभ मिलेगा। स्टेशन अधीक्षक सुधांशु मोहन ने बताया कि रेलवे ने दोनों ट्रेनों के विलय का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोचों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और नई सेवा के संचालन से रेल यात्रियों का आवागमन बेहतर बनेगा।

उन्नाव में विद्युत विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप, डीएम से कार्रवाई की मांग

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के कटरी पीपर खेड़ा गांव में विद्युत विभाग के लिए आवंटित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में सोमवार को जिला प्रशासन से शिकायत की गई। शिकायतकर्ता शिव कुमार ने जिलाधिकारी/सहायक अभिलेख अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर राजस्व अभिलेखों के आधार पर जमीन की पैमाइश और सीमांकन की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार, ग्राम कटरी पीपर खेड़ा में नेशनल हाईवे से सटी कई भूमि विद्युत विभाग को आवंटित की गई थी। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि भूमि संख्या 1164ख (रकबा 0.3350 हेक्टेयर), भूमि संख्या 1167ग (रकबा 0.2318 हेक्टेयर) और भूमि संख्या 1168 (रकबा 0.4200 हेक्टेयर) का आवंटन 3 सितंबर 2015 को विद्युत विभाग के लिए किया गया था। आरोप है कि विद्युत विभाग के नाम आवंटित इस सरकारी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि राजस्व अभिलेखों में जमीन की स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद मौके पर कब्जे की स्थिति बन रही है, जिससे भविष्य में सरकारी भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में संबंधित भूमि की मौके पर पैमाइश कराई जाए। इसके बाद राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि का सीमांकन कर विद्युत विभाग के लिए आवंटित सरकारी जमीन को चिह्नित किया जाए। यदि जांच में अवैध कब्जा पाया जाता है, तो उसे हटाकर सरकारी भूमि को सुरक्षित कराया जाए। शिव कुमार ने बताया कि सरकारी जमीन की स्थिति स्पष्ट कराने और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद को रोकने के लिए प्रशासन से शिकायत की गई है। उनका उद्देश्य है कि समय रहते जमीन की पैमाइश और सीमांकन हो जाए, ताकि सरकारी भूमि सुरक्षित रह सके। इस मामले में अब प्रशासन की जांच और राजस्व विभाग की पैमाइश के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौके पर विद्युत विभाग के लिए आवंटित भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है।

बारिश ने खोली एक्सप्रेसवे की पोल, असोहा में आठ जगह सड़क धंसी

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

कानपुर से लखनऊ के बीच 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता लगातार सवालों के घेरे में है। रोजाना कहीं-न-कहीं सड़क धंस रही है। रविवार को भी बारिश के चलते असोहा क्षेत्र में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की आठ और जगह पर सड़क धंस गई। कानपुर से लखनऊ की ओर वाली भारी वाहन लेन पर जलभराव दिखा। किलोमीटर 47.9 से लेकर 47.1 तक आठ सौ मीटर, किमी 46.6 से 46.3 तक तीन सौ मीटर तूरी के पास व किमी 45.5 पर पूरी सड़क पर बरसाती पानी भरा नजर आया। किमी 44.4 से 44.1 तक मेदपुर के पास, किमी 41.3 से 41 तक कुदिकापुर के पास और किमी 42.2 पर कई जगह दबी सड़क पर जलभराव रहा। वहीं किमी 44.6 और 40.6 पर जलनिकासी नाली टूट गई। इससे भी पानी भर गया। अचलगंज क्षेत्र में किमी 62 व 63 में भी सड़क धंसी मिली। कानपुर-लखनऊ लेन पर किलोमीटर 39.7 कांथा और किमी 30.6 बेगमखेड़ा के पास रविवार को मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर किया गया। हालांकि बीच में बारिश के चलते काम बाधित हुआ। बारिश थमने के बाद मरम्मत कार्य शुरू हुआ। इस दौरान हल्के वाहन की दोनों लेन बंद कर दी गईं। यहां पर डायवर्जन लगाकर दोनों लेन का यातायात भारी वाहन लेन से निकाला गया।

गंगा का जलस्तर छह सेंटीमीटर बढ़ा, तटवर्ती इलाकों में फिर बढ़ी चिंता

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है। रविवार तक लगातार तीन दिन की गिरावट के बाद सोमवार को जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर छह सेंटीमीटर बढ़ा है, जिससे यह चेतावनी बिंदु के बेहद करीब पहुंच गया है। वर्तमान में उन्नाव में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से महज एक सेंटीमीटर नीचे है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार शाम छह बजे गंगा का जलस्तर 111.950 मीटर था। रविवार शाम छह बजे तक इसमें दो सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई और यह 111.930 मीटर पर पहुंच गया था। इस गिरावट से तटवर्ती इलाकों के लोगों और प्रशासन ने कुछ राहत की उम्मीद जताई थी, लेकिन सोमवार को अचानक छह सेंटीमीटर की बढ़ोतरी ने स्थिति फिर बदल दी। जलस्तर में इस बढ़ोतरी के बावजूद, तटवर्ती इलाकों में पहले से जमा पानी की समस्या बनी हुई है। गोताखोर, शाही नगर, मोहम्मद नगर, चंपापुरवा, मनसुख खेड़ा, कर्बला और हुसैन नगर जैसे कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी अभी पूरी तरह नहीं उतर सका है। कई घरों के आसपास पानी जमा होने से लोगों को दैनिक आवागमन में परेशानी हो रही है। जलस्तर बढ़ने से प्रभावित इलाकों के लोगों की मुश्किलें और बढ़ने की आशंका है। कई स्थानों पर लोग अब भी नावों के सहारे आवागमन कर रहे हैं। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को पानी के बीच से निकलने में कठिनाई हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नदी का जलस्तर घटने के बाद भी जलभराव की समस्या खत्म नहीं हुई थी, और अब दोबारा बढ़ोतरी से उनकी चिंता बढ़ गई है।

यूपी में गृह-जल-सीवर कर के बकाएदारों को बड़ी राहत 15 अगस्त से शुरू होगी OTS योजना

यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में लंबित गृह कर, जल कर और सीवर कर की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का फैसला किया है।15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक चलने वाली योजना में बकाएदारों को राहत के साथ अधिकतम तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य पुराने बकाए की वसूली के साथ नगर निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और शहरों में जनसुविधाओं को बेहतर बनाना है।

उत्तर प्रदेश में गृह कर, जल कर और सीवर कर के पुराने बकाए से परेशान लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एकमुश्त समाधान योजना यानी OTS लागू करने का फैसला लिया है। योजना का उद्देश्य लंबे समय से लंबित संपत्ति कर की वसूली को आसान बनाना, करदाताओं को व्यावहारिक राहत देना और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के नेतृत्व में शुरू की जा रही इस योजना का लाभ प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों के करदाताओं को मिलेगा। सरकार के मुताबिक, योजना के जरिए पुराने बकाएदारों को भुगतान का आसान विकल्प मिलेगा, जिससे एक साथ बड़ी रकम जमा करने का दबाव भी कम होगा।OTS योजना 15 अगस्त 2026 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। सरकार ने योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 15 अगस्त से 14 सितंबर तक प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने का फैसला किया है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा बकाएदारों तक योजना की जानकारी पहुंचाना और उन्हें इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करना है।सरकार ने बकाया संपत्ति कर जमा करने के लिए अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा भी दी है। नियमों के मुताबिक, योजना शुरू होने के 30 दिनों के भीतर बकाएदार को कुल बकाया राशि का एक-तिहाई हिस्सा जमा करना होगा। इसके बाद बची हुई दो-तिहाई राशि को अगले दो महीनों में दो बराबर मासिक किस्तों के जरिए जमा किया जा सकेगा। यानी बकाएदारों को भुगतान के लिए चरणबद्ध सुविधा मिलेगी, लेकिन निर्धारित समयसीमा में पूरा भुगतान करना जरूरी होगा।नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य केवल बकाया कर की वसूली करना नहीं है, बल्कि नगर निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना भी है। लंबे समय से अटके राजस्व की वसूली होने से नगर निकायों के पास विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।सरकार का कहना है कि इस राजस्व का इस्तेमाल शहरों में सड़क, जल निकासी, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा। साथ ही पुराने कर विवादों और न्यायालयों में चल रहे मामलों में भी कमी आने की उम्मीद है।कुल मिलाकर, OTS योजना एक तरफ बकाएदारों को पुराने करों के भुगतान में राहत देगी, वहीं दूसरी तरफ नगर निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने में मदद करेगी। अब देखना होगा कि 15 अगस्त से शुरू होने वाली यह योजना कितने बकाएदारों को अपने दायरे में ला पाती है।

समाजवादी पार्टी ने घोसी सीट से दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित किया

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच मऊ जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बहुजन समाज पार्टी (BSP) के बाद अब समाजवादी पार्टी (SP) ने भी जिले की एक विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सोमवार को मऊ पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने घोसी विधानसभा सीट से दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी ने घोसी विधानसभा सीट के लिए सुजीत सिंह को मैदान में उतारने का फैसला किया है। सुजीत सिंह दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे हैं। सुजीत सिंह घोसी से पूर्व विधायक रहे सुधाकर सिंह के बेटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुजीत सिंह 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उनके दो भाई और एक बहन हैं। वह सबसे छोटे हैं। उनके एक भाई का नाम अजीत प्रताप है। वहीं दूसरे भाई का नाम अमित सिंह है। सुजीत सिंह ने भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे से 2013 में MBA किया। बताया जाता है कि वह अपने बैच के टॉपर भी रहे। इसी वजह से उन्हें विश्वविद्यालय की तरफ से गोल्ड मैडल भी दिया गया। 2015 में सुजीत ने शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से इकोनॉमिक्स में PHD की डिग्री भी हासिल की।बता दें कि कुछ महीने पहले सुधाकर सिंह का निधन हो गया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने सोमवार को मऊ में उनके नाम की घोषणा की। सपा से पहले बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने मऊ जिले की 2 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं।

बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान,खोले कई राज

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणियों और यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। गोंडा में उन्होंने मामले से जुड़े पहलवानों, अखाड़े और राजनीतिक कनेक्शन को लेकर अपनी बात रखी। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस कोच और अखाड़े का नाम मामले में सामने आया है, वह एक तरह से हुड्डा परिवार के लिए काफी खास रहा है। उनके मुताबिक, हरियाणा के दूसरे अखाड़ों के पहलवानों की तुलना में इसी खास अखाड़े से बड़ी संख्या में खिलाड़ी सामने आए। उन्होंने दावा किया कि यह बात अदालत के फैसले में भी सामने आई है। बृजभूषण ने कहा कि जिन दो पहलवानों ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे, उन्होंने जज के चैंबर में हुई बातचीत और घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया था। उनका कहना है कि अदालत ने इन बयानों को रिकॉर्ड पर लिया और बाद में इन्हीं गवाहियों के आधार पर फैसला सुनाया गया। उन्होंने मामले से जुड़ी एक और बात का जिक्र करते हुए कहा कि अलग-अलग जिलों से आने वाले पहलवानों ने अपना एक ही पता दर्ज कराया था। बृजभूषण के अनुसार, इन सभी के रिकॉर्ड में सोनीपत स्थित बजरंग पूनिया का आवास पता बताया गया था। पूर्व भाजपा सांसद ने मामले में राजनीति के एंगल पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर हुड्डा परिवार सबसे पहले सामने आया था। बृजभूषण ने कहा कि अब यह देखना होगा कि आगे उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। गौरतलब है कि पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद यह मामला लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय कुश्ती में चर्चा का विषय रहा। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद वह लगातार मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि, बृजभूषण शरण सिंह द्वारा लगाए गए राजनीतिक संबंधों और अन्य दावों को उनके बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

अलीगढ़ का नाम 'हरिगढ़' करने की चर्चाओं के बीच पार्षदों ने जताया विरोध

अलीगढ़ का नाम बदलकर 'हरिगढ़' किए जाने की चर्चाओं ने शहर की सियासत को गरमा दिया है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के पार्षद एक मंच पर आ गए हैं। विपक्षी पार्षदों ने एकजुट होकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश की राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर नाम न बदलने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के लिए विपक्षी दलों के पार्षद कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए और शहर का नाम बदले जाने की चर्चाओं पर कड़ा ऐतराज जताया। पार्षदों का कहना है कि अलीगढ़ का नाम बदलना शहर के मूल स्वरूप को प्रभावित करेगा। उन्होंने जिलाधिकारी (DM) के जरिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि शहर का नाम वर्तमान स्थिति में ही बरकरार रखा जाए। विपक्षी पार्षदों ने कहा कि अलीगढ़ पूरी दुनिया में अपनी 'ताला, तालीम और तहजीब' की खास पहचान के लिए जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक शहर है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी समुदायों के लोग लंबे समय से आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ रहते आए हैं। पार्षदों ने यह भी कहा कि नगर निगम की किसी भी हालिया बैठक में नाम बदलने से जुड़ा कोई आधिकारिक प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। साल 2022-23 में केवल एक सुझाव सामने आया था, जिसका उस दौरान भी कड़ा विरोध किया गया था। प्रदर्शनकारी पार्षदों ने कहा कि नगर निगम के पास किसी भी जिले का नाम बदलने का कानूनी अधिकार नहीं होता, यह फैसला केवल शासन स्तर पर ही लिया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नाम परिवर्तन की बातें केवल जनता को गुमराह करने और वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास हैं।